VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1247)

Name of Candidate	Manoj Kumar		
Medium Eng./Hindi	Hindi	**Registration Number**	62755
Center	Jaipur	**Date**	3-9-19

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. **Contextual Competence**
2. **Content Competence**
3. **Language Competence**
4. **Introduction Competence**
5. **Structure - Presentation Competence**
6. **Conclusion Competence**

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. Mention the structure and functions of NITI Aayog. Also, comment on its contemporary relevance. **(150 words) 10**

नीति (NITI) आयोग की संरचना और प्रकार्यों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर भी टिप्पणी कीजिए।

भारत सरकार द्वारा कार्यकारी राष्ट्रपति आदेश से योजना आयोग को विस्थापित कर नीति आयोग की स्थापना की गई।

प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन / अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष तथा इसके साथ ही स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों से बनी एक पीठ होगी।

नीति आयोग के कार्य

1) राष्ट्रीय सुरक्षा के आलोक में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन
2) विकेन्द्रीकृत नियोजन को सक्षम बनाना (बॉटम टू टॉप अप्रोच)
3) थिंक टैंक के रूप में पॉलिसी इनपुट प्रदान करना
4) संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करना

समकालीन प्रासंगिकता

1) सहकारी एवं प्रति स्पर्धी संघवाद का सृजन करना जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम

2) डेटा आधारित योजनाओं की मूल्यांकन प्रणाली एवं प्रशासन को गतिशील करना (~~SATH~~ SATH - एवं SATH-E (एजुकेशन))

3) सरकारों हेतु इंडिकेटर विकसित करना (समग्र जल सूचकांक)

4) ~~को~~ नीति आयोग द्वारा राज्यों को अपनी रणनीति बनाने एवं कार्यान्वयन स्तर पर सुधार मे नीति आयोग का सुधार - साक्ष्य आधारित मूल्यांकन प्रणाली

इस प्रकार नीति आयोग नीति क्रियान्वयन एवं निर्माण के स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इसको वित्तीय स्वायत्ता प्रदान कर संगठन के स्तर पर इसकी क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Critically discuss the practice of setting up Fast Track Courts to reduce pendency of cases in the judiciary. **(150 words) 10**

न्यायालयों में लंबित वादों को कम करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थापित करने की कार्यप्रणाली की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।

वल्ड सर्वे : भारतीय न्यायालयों की स्थिति के प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय न्यायालयों में 3.5 करोड़ मामले लम्बित पड़े हैं। वस्तुत: इनके समाधान हेतु एक विकल्प के रूप में फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थापित किया जाता है

फास्ट ट्रैक कोर्ट एक ही प्रकार के मामलों को चुनते हैं अत: वादों की लिस्टिंग स्वीकरण सही ढंग से हो जाता है जिससे जल्दी निर्णयन में सहायता मिलती। इसकी शुरुआत सन् 2000 में हुयी।

स्थापना प्रणाली

2000 में इनका निर्माण निश्चित समयावधि हेतु किया किन्तु आगे इसका समय बढ़ाया जा सकता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

फास्ट ट्रैक कोर्ट से सम्बन्धित समस्या

- आवश्यक अवसंरचना (वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग) का अभाव
- कोई प्रशिक्षित न्यायिक नियुक्ति नहीं
- पुलिस द्वारा चार्जशीट एवं याचिका का खराब स्तर
- वकीलों एवं जज की स्थगन की प्रवृत्ति
- फास्ट ट्रैक कोर्ट में गवाही की क्रॉस एग्जामिनेशन न कर पाने की घटनाएं।

वस्तुतः भारतीय संविधान हालांकि न्याय की गारंटी प्रदान करता है किन्तु हम ऐसी व्यवस्था के निर्माण से अब भी दूर हैं जहाँ प्रत्येक नागरिक को समय पर समुचित न्याय मिल सके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Highlight the challenges faced by lower judiciary in India and suggest measures for enhancing their productivity. **(150 words) 10**

भारत में निचली अदालतों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने हेतु उपायों का सुझाव दीजिए।

भारत में एकल न्यायपालिका को अपनाया गया है जहाँ निचले स्तर पर सेशन कोर्ट स्थापित किए जाते हैं किंतु इन निचली अदालतों द्वारा निम्न प्रकार की चुनौतियों का सामना किया जाता है-

(1) सतत भर्ती प्रक्रिया के अभाव के कारण पदों की रिक्तियाँ

2) भावी पदोन्नति के सीमित अवसर के कारण टैलेण्ट पूल का कम आकर्षण

3) स्थगन प्रवृत्ति अधिक होने के साथ दबावों के कारण निम्न स्तरीय निर्णय

4) खराब अवसंरचना के चलते तकनीकों का उचित प्रयोग नहीं।

उत्पादकता सुधार हेतु उपाय

1) पदोन्नति के पर्याप्त अवसर दिए जाए एवं कार्य की एकाधिकारवादिता नियंत्रित हो।

2) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का निर्माण कर जजत्र आपूर्ति का सुनिश्चय

3) आवश्यक अवसंरचनात्मक सुधार

4) कोर्ट में लिस्टिंग केस की व्यवस्था में सुधार हो।

वस्तुतः इन उपायों द्वारा भारतीय न्यायपालिका के मूल आधार से परखकर फिर लाने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Assess the need to formalise the process of post-legislative scrutiny to improve the effectiveness of laws. **(150 words) 10**

कानूनों की प्रभावशीलता में सुधार के लिए विधि-निर्माण पश्चात् संवीक्षा की प्रक्रिया को औपचारिक बनाने की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए।

किसी कानून की सफलता हेतु उसका समय सापेक्ष एवं प्रभावी होना आवश्यक है अतः कानून निर्माण उपरांत संवीक्षा प्रक्रिया को औपचारिक करने से निम्नलिखित लाभ होंगे —

1) कानूनों के रूप-रेखा की जानकारी प्राप्त करना
2) कानून के प्रति प्रभावक समूहों का दृष्टिकोण फीडबैक के रूप में प्राप्त करना
3) कानूनी अध्यारोपण, अस्पष्टता की जांच
4) कानून के प्रवर्तन के सम्बन्ध में विधि को कानून के महत्वपूर्ण अवधि, मुख्य-रूप में सुधार

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5) सिद्धान्त बनाम व्यवहार की असंगतता की समस्या का समाधान प्रस्तुत करना

6) महत्वपूर्ण व्यक्तियों के समूह द्वारा तथा प्रवर्तन इकाईयों द्वारा मानकों की भारती पूर्तियों का समावेश करना

7) विधि निर्माण के साथ क्रियान्वयन प्रक्रिया का स्पष्टीकरण।

इस प्रकार औपचारिक नीतिगत प्रक्रिया विधि निर्माण के स्तर पर महत्वपूर्ण सुधार साबित हो सकती है तथा प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक होगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Discuss the potential of Artificial Intelligence (AI) in improving the effectiveness of e-governance in India. **(150 words) 10**

भारत में ई-गवर्नेंस की प्रभावशीलता में सुधार लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की क्षमता की विवेचना कीजिए।

ई-गवर्नेन्स से तात्पर्य शासन प्रक्रिया में निर्णयों एवं सेवा आपूर्ति के सम्बंध में संचार प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटर इत्यादि डिजीटल साधनों का प्रयोग है

ई-गवर्नेन्स के कार्य
- लाभार्थी लक्षीकरण
- सेवा आपूर्ति
- सूचना का प्रसारण
- FAQ
- शिकायत निवारण
- निर्देशन एवं मॉनिटरिंग

कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं ई-गवर्नेन्स

- सरकारी डेटा का विश्लेषण एवं प्रतिरूप निर्धारण कर Trend setting करना
- शिकायतों को विभागों में अग्रेषित करना
- प्रशासनिक लेन-देन की निगरानी

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- अनुपयुक्त प्रशासनिक सेवकों को भेजना
- कृत्रिम इंटेलिजेंस सूचना प्रणाली का विकास

वस्तुतः AI का प्रयोग प्रशासन में सूचनाओं का संग्रहण, शिकायतों के निवारण के अंतर्गत इत्यादि कार्यों में किया जा सकता है जिससे प्रशासनिक कार्यबल का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में किया जा सकेगा।

प्रशासन में AI

- उपलब्ध सूचना का विश्लेषण ↓ प्रतिरूप निर्माण
- जनता व्यवहार विश्लेषण एवं नीति निर्माण
- Geo-mapping का योजना प्रदेश का निर्माण
- ग्रीविएंस रिड्रेसल ट्रैकिंग → संबंधित विभाग को भेजना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Despite various reforms in the public grievance redressal mechanisms, their effectiveness remain limited. Discuss. (150 words) 10

लोक शिकायत निवारण प्रणाली में विभिन्न सुधारों के बावजूद, उनकी प्रभावशीलता सीमित बनी हुई है। चर्चा कीजिए।

किसी भी प्रशासनिक संगठन की नागरिक उन्मुखता का आकलन उसकी लोक सेवा शिकायत निवारण प्रणाली द्वारा किया जाता है।

लोक शिकायत प्रणाली में सुधार

- कार्मिक एवं लोक सेवा मंत्रालय के अधीन शिकायत निवारण प्रणाली का गठन किया गया है।
- सिटीजन चार्टर में शिकायत सम्बन्धी विकल्प प्रदान किए गए हैं।
- ई-गवर्नेंस द्वारा सेवा उपलब्ध कराना एवं शिकायतों की ई-फाइलिंग

सीमित प्रभावशीलता के कारण

1) प्रशासनिक - इनर्शिया - पुराने मानसिक

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मानासन से बाहर न निकलना।

2) स्टाफिंग की कमी एवं रिक्तियाँ

3) जनसंपर्क में भागीदारी का अभाव एवं व्यक्तिगत व्यस्तता

4) प्रशासन में खेल की ~~नीतिगत~~ सीमित संभावना एवं प्रशासनिक अभिरुचि

5) समुचित पुरस्कार नीति का अभाव

वस्तुतः इन कारणों से भारत में लोक शिकायत प्रणाली अपनी वास्तविक क्षमताओं के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाती है जिस प्रकार अपेक्षित है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. Explaining the factors that contribute to trafficking of women and children in India, highlight the steps taken in recent times to combat it. **(150 words) 10**

भारत में महिलाओं और बच्चों की तस्करी में योगदान देने वाले कारकों की व्याख्या करते हुए, इससे निपटने के लिए हाल के दिनों में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं। इन उपबंधों के विपरीत भारत में महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी की घटना के निम्नलिखित कारण हैं —

1) अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की छिद्रिल प्रकृति के कारण भारत से 'माइग्रेंट - स्मगलिंग' एवं भारत में उन्हें दास बनाना

2) गरीबी एवं जागरूकता के कारण मानव दुर्व्यापार - बाल श्रम

3) महिलाओं का यौन कर्मी एवं बच्चों का भिक्षा में प्रयोग

4) मानव अंगों की भारी कमी एवं तस्करी से प्राप्त लोगों के मानव अंग निकालना

5) पीड़ितों के ज्ञान का अभाव एवं उपलब्ध सहायता का लाभ न लेने पाना

निपटने हेतु हालिया कदम -

1) मानव इच्छाधारा रोकथाम 'अधिनियम' द्वारा उनके प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास का प्रावधान

2) ऑपरेशन 'मुस्कान' द्वारा गुमशुदा बच्चों की पहचान

3) पैनल पोर्टल द्वारा बालकों की पहचान

वस्तुतः इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं जिनका सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु न्याय की स्थापना हेतु आवश्यक है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. With Vector-Borne Diseases (VBDs) reaching epidemic proportions in India, highlight the factors that have led to their emergence. Also, suggest some measures for their effective control and management. **(150 words) 10**

भारत में रोगाणुवाहक-जनित रोग (VBDs) महामारी की तरह उभरकर सामने आये हैं, अतः उन कारकों को रेखांकित कीजिए जिनके कारण इनका उद्भव हुआ है। साथ ही, इनके प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन हेतु कुछ उपायों का भी सुझाव दीजिए।

भारत में मलेरिया के बाद डेंगू एवं अब जापानी बुखार जैसे रोगाणुवाहक जनित रोगों ने क्रमिक रूप से आकर बच्चों के महामारी का रूप लिया है।

रोगों के उद्भव के कारण

1) जलवायु परिवर्तन के कारण रोगाणुवाहकों के प्रसार-क्षेत्र (Range) में वृद्धि हुयी है।
(+) भारत की मानसूनी जलवायु
2) भारतीयों के कुपोषण के स्तर एवं अस्वच्छता के कारण इन रोगों के प्रति सुभेद्यता अधिक है।

3) खराब प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना के चलते ये रोग महामारी की श्रेणी में परिवर्तित हो जाते हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रणाली नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु उपाय

1) उत्पत्ति क्षेत्रों यथा जल भराव इत्यादि का समाधान (विशेषतः तराई क्षेत्र)

2) (स्वच्छता से आरोग्य) स्वच्छता का प्रसार

योजना की शुरुआत

3) पोषण स्तर में सुधार एवं रोगाणु प्रतिरोध में सुधार

4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की क्षमता में उन्नयन

5) प्रतिरोधक टीकों का निर्माण उदा. मॉस्क्वीरिक्स (मलेरिया)

इन उपायों द्वारा वेक्टर ~~जनित~~ जनित रोगों की समस्या का समाधान कर sdg 3 स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति निश्चित होगी।

9. After years of neglect, rapidly evolving regional strategic realities are now forcing India and Indonesia to coordinate their policies ever more closely. Discuss. **(150 words) 10**

वर्षों की उपेक्षा के बाद, तेजी से विकसित हो रही क्षेत्रीय रणनीतिक वास्तविकताएं अब भारत और इंडोनेशिया को और अधिक घनिष्ठता से अपनी नीतियों को समन्वित करने के लिए बाध्य कर रही हैं। चर्चा कीजिए।

हाल ही में भारत एवं इंडोनेशिया के मध्य रणनीतिक एवं राजनीतिक सम्बन्ध प्रगाढ़ हुये है।

भारत - इंडोनेशिया सम्बंधी रणनीतिक वास्तविकता एवं हितों की उपस्थिता

हिन्द क्षेत्र में चीन का आक्रामक होना एवं अपनी सम्प्रभुता की रक्षा

नियम आधारित वैश्विक सम्बंध प्रणाली का निर्माण एवं क्षेत्रीय शांति

व्यापार एवं विकास द्वारा क्षेत्रीय एकीकरण की प्राप्ति

इन नाजुक मांगों के चलते दोनों देशों में घनिष्ठता आयी है भारत द्वारा ~~मलेशिया~~ इंडोनेशिया के सबांग में नौसैन्य अड्डे की स्थापना की गयी।

वस्तुतः यह क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा की दशा के सन्दर्भ में दोनों देशों की रणनीतिक वास्तविकता है कि वे मिलकर सुरक्षा एवं नियमों के मुद्दे पर एकजुट हों।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Despite several attempts at resetting the ties, various barriers continue to be a cause of concern in the India-Nepal bilateral relations. Discuss.

(150 words) 10

संबंधों को पुन: स्थापित करने के कई प्रयासों के बावजूद, भारत-नेपाल द्विपक्षीय संबंधों में विभिन्न अवरोध निरंतर चिंता का कारण बने हुए हैं। चर्चा कीजिए।

भारत-नेपाल सम्बंध भारत-नेपाल मैत्री संधि पर आधारित है जिसके आधार पर नेपाली नागरिकों को भारत में कई अधिकार प्राप्त हैं वहीं भारत का नेपाल की विदेश नीति एवं अर्थनीति पर प्रभाव है।

इसके अलावा भारत द्वारा सम्बंधों में दूरी के समाधान हेतु वार्ता तंत्र की स्थापना कार्यक्रमों की घोषणा सम्बंधी कई प्रयास किए गए किंतु निम्नांकित अवरोध चिंता के कारण हैं-

1) नेपाल में सत्ताधारी दल की चीन के प्रति निकटता एवं भारत विरोधी प्रचार

2) नेपाल के संविधान में मधेशी लोगों का मुद्दा एवं भारत के इस सम्बंध में

हित

3) नेपाल द्वारा उत्पादित जल विद्युत हेतु बाजार की खोज

4) व्यापार को विविधिकृत करने हेतु चीन का सहयोग प्राप्त करना एवं कलकत्ता बंदरगाह पर निर्भरता कम करना।

5) बोडोलैंड का मुद्दा

6) नेपाल के माध्यम से तस्करी एवं अपराधियों की शरणगाह

7) नेपाल में कुछ वर्ग द्वारा ग्रेटर नेपाल (कुमाऊं) का प्रोपोगेंडा चलाना

वस्तुत: इन मुद्दों का समाधान कर क्षेत्रीय एकीकरण को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य के विकास द्वारा शांति स्थापना एवं जनों के कल्याण की दिशा उत्पन्न हो।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Delineate the differences between pressure groups and interest groups. Citing examples, elaborate on the ways in which pressure groups influence government decisions and policy making in India. **(250 words) 15**

दबाव समूहों और हित समूहों के मध्य अंतर का वर्णन कीजिए। उदाहरणों को उद्धृत करते हुए, उन तरीकों का सविस्तार वर्णन कीजिए जिनके माध्यम से दबाव समूह भारत में सरकारी निर्णयों और नीति-निर्माण को प्रभावित करते हैं।

दवाब समूह ऐसे संगठित समूह होते है जो प्रत्यक्ष रूप से दल निर्माण कर सत्ता प्राप्त नहीं करते किंतु धन बल, जन दवाब एवं प्रदर्शन द्वारा परोक्ष रूप से सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं, उदाहरण- अखिल भारतीय पिछड़ा संघ, मजदूर किसान संघर्ष समीति ।

हित समूह संगठन का बड़ा स्तर होता है जो किसी विशिष्ट हितों पर बल देते है। दवाब समूह हित समूह का एक भाग होते हैं। वस्तुत: इन दोनों में मुख्य अंतर हित समूह द्वारा किसी विशिष्ट हित की प्राप्ति वहीं दवाब समूह नीति पर सतत प्रभाव बनाए रखता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

	हित समूह	दबाव समूह
उद्देश्य	एकल समान हित संगठन	हितों का सुमुच्चीकरण।
संगठन	सामान्य एवं पदानुक्रम के साथ, गैर लाभकारी रूप में	कम्पनी के रूप में कार्य करते हैं।

दबाव एवं हित समूहों की कार्य पद्धति

① धन एवं अर्थनीति का प्रयोग- असंवैधानिक रूप से विधायी सदस्यों को प्रश्न पूछने, मतदान से उपस्थित रहने या कानून बनाने हेतु रिश्वत के रूप में प्रयोग (क्रोनी केपटिलिज्म)

2) जनता के मध्य मुद्दे का प्रचार एवं राजनैतिक गतिशीलता उत्पन्न करना। जिससे जन दबाव द्वारा निर्णयों को प्रभावित करना उदाहरण- मराठा आरक्षण

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3) सरकार के समक्ष वैधानिक सूचना प्रकटीकरण एवं हित स्पष्टीकरण करना वस्तुतः सहभागिता का प्रयोग उदाहरण - श्रम कानून में सुधार हेतु श्रम यूनियन

4) न्यायालय में वाद के माध्यम से उदाहरण नाज फाउण्डेशन द्वारा समलैंगिकता के सम्बंध में

इस प्रकार इन समूहों ने भारतीय नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है हालांकि इनके विनियमन का अभाव नई तरह प्रभाव डालता है किन्तु यह लोकतंत्र को समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. Highlighting the issues faced by the institutions of local self governance in India, suggest measures that can be taken to improve their effectiveness in the delivery of public goods and services at the grassroot level.

(250 words) 15

भारत में स्थानीय स्व-शासन की संस्थाओं द्वारा समाना की जा रही समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए, जमीनी स्तर पर सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण की प्रभावशीलता में सुधार लाने हेतु किए जा सकने वाले उपायों का सुझाव दीजिए।

भारत में तृणमूल लोकतंत्र की स्थापना हेतु 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया किंतु वास्तव में ये संस्थाएं आरम्भ से ही कुछ समस्याओं से ग्रस्त रहे हैं।

1) वित्त की समस्या पर्याप्त कराधान कर आधार की व्यवस्था नहीं है उदाहरण हेतु देश के नगर 60% जीडीपी के एवं 30% जनसंख्या के केन्द्र है जबकि कर अंश आनुपातिक रूप से बहुत कम है। जिससे दायित्वों की आपूर्ति नहीं हो पाती

इसके साथ ही राज्य वित्त आयोग का नियमित गठन न होना एवं इनके प्रतिवेदनों पर

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सरकार द्वारा ध्यान न दिया जाना भी एक समस्या है।

इसके साथ जी.एस.टी (GST) के आने से कर प्राधिकार में और अस्पष्टता आ गयी है।

2) विषयों की अपर्याप्तता क्योंकि पंचायत राज्य सूची का विषय है एवं विषय हस्तांतरण की शक्ति राज्यों के निहित किन्तु पर्याप्त एवं वास्तविक शक्ति हस्तांतरण नहीं किया गया है।

3) इसके अतिरिक्त समर्पित प्रशासनिक मशीनरी एवं क्रियान्वयन कार्य बल का अभाव।

4) dpc/MPC का प्रभावी भूमिका न निभा पाना

5) स्वयं सहायता समूहों SHG के साथ अस्वस्थ स्पर्द्धा एवं SHG द्वारा समान कार्य करना

6) महत्वपूर्ण योजनाओं (स्मार्ट सिटी) में इन संस्थाओं की अनदेखी।

उपाय जिनसे सेवा वितरण में सुधार लाया जा सके

1) सामाजिक अंकेक्षण तथा विकेन्द्रीकृत नियोजन को मजबूत बनाया जाए एवं जांच के माध्यम से भ्रष्टाचार एवं रिसाव पर अंकुश लगाया जाए

2) मांग-प्रेरित उपाय एवं सेवा आपूर्ति हेतु क्षेत्राधारित योजना निर्माण पर साइज फिट ऑल उपागम नहीं।

3) स्थानीय निकायों की मजबूती हेतु वित्त, विषय, प्रशासनिक सहयोग की आपूर्ति द्वारा लक्षितों के पहचान, प्रशासन एवं सेवा वितरण में सटीकता लायी जाए

वस्तुतः तृणमूल इकाईयाँ शासन की प्रभावशीलता एवं सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार लाकर सुशासन की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

13. The recent amendment to the Right to Information Act, 2005 will weaken the act and undermine the authority of Information Commissioners. Discuss. **(250 words) 15**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में हालिया संशोधन इस अधिनियम को कमजोर बनाएगा और सूचना आयुक्तों के प्राधिकार को क्षीण करेगा। चर्चा कीजिए।

(RTi) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 शासन प्रशासन में पारदर्शिता लाकर प्रश्न पूछने की संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके द्वारा सूचना जानने को भाग-III के अनुच्छेद 19 का भाग बनाया गया है।

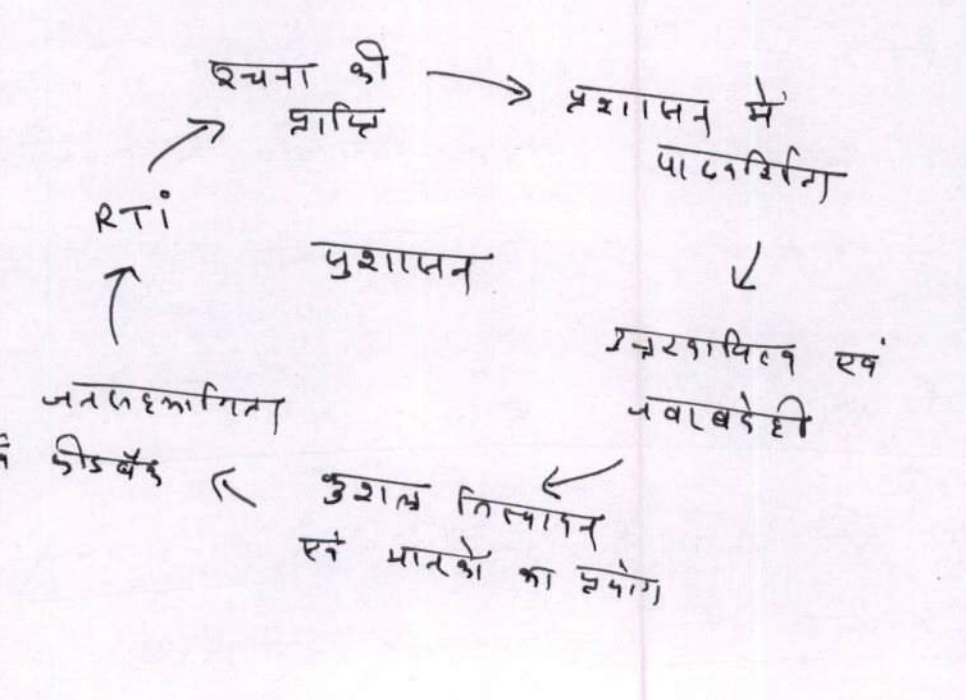

धारा 8 में किए गए संशोधन

विषय	संशोधन पूर्व	संशोधन उपरांत
कार्यकाल सम्बंधी	मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान 5 वर्ष	केन्द्र सरकार निर्धारित करेगी
वेतन सम्बंधी	सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश के समान	केन्द्र द्वारा निर्धारित किया जाएगा
पेंशन सम्बंधी	वेतन से पेंशन प्राप्त राशि को घटा दिया जाता था	प्रावधान हटा दिया

सरकार का तर्क है कि सूचना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है अतः इसे निर्वाचन आयोग के समान दर्जा देना सही नहीं जबकि यह सूचना आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष बना देती है जो उचित नहीं है।

अधिनियम RTI को कमजोर कैसे करेगा?

1) पद एवं वेतन के सम्बंध में केन्द्र सरकार की प्रभावी भूमिका फलत: पद की गुरुता,

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

वेतन में लाभकारी / अलाभकारी परिवर्तन के कारण सूचना आयुक्तों का कार्य के आचरण की स्वतंत्रता प्रभावित होगी।

2) आयुक्त यदि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों के समकक्ष नहीं होंगे तो प्रशासनिक इकाई, नौकरशाहों द्वारा अवहेलना की आशंका बनी रहती है।

3) संस्थागत रूप से RTI को कमजोर करता है एवं भूमिका के आलोक में महत्ता को नहीं रखता है।

वस्तुत: यह पीछे की ओर लौटने वाले कदम है आवश्यकता RTI के सशक्तिकरण द्वारा इसकी जनता का उपयोग सुशासन हेतु करने की है जिससे भारतीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में बदला जाए किंतु हालिया संशोधन इसके नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Highlight the process of delimitation in India. Also, throw light on the debates surrounding the delimitation exercise in India. **(250 words) 15**

भारत में परिसीमन की प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए। साथ ही, भारत में परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर होने वाले वाद-विवादों पर भी प्रकाश डालिए।

परिसीमन आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तत्वाधान में किया जाता है जिसके अनुसार प्रत्येक जनगणना उपरान्त संसद द्वारा परिसीमन का आयोजन कराया जाएगा।

भारत में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है अन्तिम बार परिसीमन अधिनियम 2002 द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया गया था

<u>परिसीमन आयोग का कार्य</u>

- यह देश में विधानसभा चुनावों संसदीय चुनाव क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है।
- यह जनसंख्या एवं निर्वाचितों के अनुपात को बनाए रखता है ताकि संख्यात्मक विषमता उत्पन्न न हो।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- जनगणना अनुसार SC/ST सीटों का निर्धारण उपरोक्त कार्य परिसीमन आयोग द्वारा किए जाते हैं एवं इनके निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

~~परिसीमन~~ परिसीमन आयोग 2002 द्वारा इन कार्यों का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया।

परिसीमन प्रक्रिया को लेकर विवाद

1) क्षेत्रों की परिवर्तनशीलता प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों में बाधा पहुंचाती है। क्षेत्र A के लोग क्षेत्र C में चला जाता जो जिले के रूप में B का भाग है एवं यह B व परिसीमन क्षेत्र में है

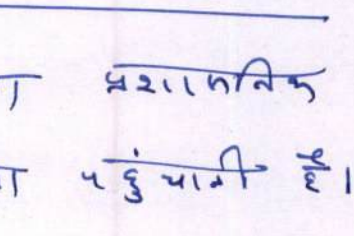

(2) जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन एवं नियंत्रण करने वाले राज्यों पर प्रगति का एक

रूप क्योंकि जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य अब अधिक सीट प्राप्त कर सकेंगे।

3) गैरी-मेण्डरिंग की भांति सत्ताधारी दल द्वारा क्षेत्र का वर्गीकरण करना एवं स्वयं के मताधार द्वारा सीमांकन में हस्तक्षेप कर चुनावी विजय प्राप्त करना

4) जनसंख्या के बजाय सामाजिक-सांस्कृतिक विशिष्टता की पहचान की जानी चाहिए। सीमांकन वास्तविक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व नहीं करता।

वस्तुतः चुनावी परिसीमन से प्रतिनिधित्व, आकार एवं अनुपात, प्रतिनिधित्व तथा चुनावी रणनीति जैसे महत्वपूर्ण विवादित प्रश्न विद्यमान हैं किन्तु निःसंदेह यह लोकतंत्र को वास्तविक प्रतिनिधित्वात्मक स्वरूप प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण व्यवस्था है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Self Help Groups (SHGs) are vehicles of rural development, which help in the upliftment of marginalized groups. Elucidate. Further, mention the constraints faced by SHGs and how they can be addressed. **(250 words) 15**

स्वयं सहायता समूह (SHGs) ग्रामीण विकास के वाहक हैं तथा ये हाशिए पर मौजूद समूहों के उत्थान में सहायता करते हैं। स्पष्ट कीजिए। साथ ही, SHGs द्वारा सामना की जा रही बाधाओं का उल्लेख कीजिए। इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है।

स्वयं सहायता समूह 5-20 लोगों का समूह होता है जो आपसी भागीदारी एवं आर्थिक सहयोग द्वारा वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

<u>ग्रामीण विकास में भूमिका</u>

1) लघु बचत आदतों की बढ़ोतरी एवं आगे निवेश का अवसर

2) स्वरोजगार हेतु वित्त आपूर्ति एवं गरीबी उन्मूलन

3) ऋण दुष्चक्र से छुटकारा एवं जीवन स्तर में सुधार

4) <u>संयुक्त उद्यम संचालन एवं रोजगार सृजन</u>

5) वित्तीय साक्षरता, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण का केंद्र प्रदान करना

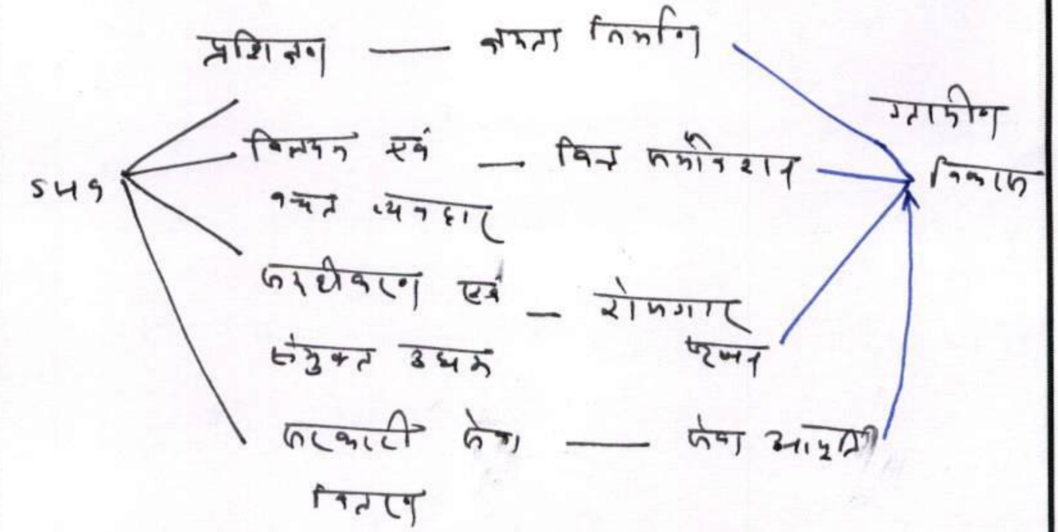

SHG की वर्तमान की बाधा

- SHG बैंक लिंकेज की सीमित सफलता एवं कोलेटरल के अभाव में SHG की संस्थागत ऋण तक कम पहुंच

- SHG हेतु प्रशिक्षण एवं उद्यमिता विकास हेतु सरकारी प्रयास प्रभावी नहीं रहे हैं।

- पंचायती राज के साथ आपसी प्रतिस्पर्धा एवं कार्यों के निर्धारण में सहमति का अभाव

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- SHG के क्षेत्रीय वितरण में असमानता एवं उत्तर भारत में असफल

- पितृसत्तात्मक एवं लैंगिक विभेद के कारण महिलाओं की सीमित गतिशीलता

- SHG का आगे क्रमिक रूप से बढ़कर co-ऑपरेटिव के स्तर पर न बढ़ पाना।

बाधाओं का हल

1) बिना कोलेटरल ऋण एवं वित्तीय समावेशन
2) कौशल अभियान के तहत प्रशिक्षण एवं इन्क्यूबेशन
3) उद्यम स्थापित कर आयाम को बढ़ाना। 'स्फूर्ति' योजना का प्रयोग SHG के सम्बन्ध में।
4) सरकारी सेवा आपूर्ति हेतु इनका प्रयोग
5) प्रशासनिक एवं बैंकिंग मानसिकता में परिवर्तन

वस्तुतः इस प्रकार SHG की संगठित ऊर्जा का प्रयोग ग्रामीण एवं महिला विकास में किया जा सकता है जिससे New India के विजन की प्राप्ति संभव हो पाएगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. With construction of toilets being only one part of the solution for a clean India, it is time that the Swachh Bharat Mission puts more emphasis on the other facets as well. Discuss. **(250 words) 15**

शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत के समाधान का केवल एक भाग है, अतः अब समय आ गया है कि स्वच्छ भारत मिशन अन्य पहलुओं पर भी अधिक बल दे। चर्चा कीजिए।

महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर 2014 से भारत सरकार द्वारा 5 वर्षों के भीतर 2019 तक खुले में शौच की प्रथा की समाप्ति हेतु स्वच्छ भारत मिशन का आरम्भ किया गया।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन किया गया एवं पूरे भारत के शौचालयों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गयी परिणाम स्वरूप हैं भारत के शौचालयों वाले घरों का % 44 से बढ़कर 94% (+) हो गया एवं साथ ही प्रयोग के स्तर पर भी महत्वपूर्ण सुधार आये है

इनके परिणाम स्वरूप शहरों, जिलों एवं राज्यों को odf (ओपन डेफीकेशन फ्री) घोषित प्रदान किया गया है जैसे. हिमाचल, गुजरात इत्यादि ।

किंतु यह स्वच्छता के मानदण्ड हेतु पर्याप्त नहीं है बल्कि आरंभिक प्रगति मात्र है

स्वच्छता का आयाम

अपशिष्ट स्वच्छता
- ठोस कचरा प्रबंधन एवं समुचित निष्पादन प्रणाली

शौचालय सम्बंधी
- A) शौचालय निर्माण एवं प्रयोग
- B) मल पदार्थों के अपशिष्ट का निपटान
- C) सीवर प्रणाली को दुरुस्त करना
- D) जल का पुनर्चक्रण

स्वच्छ वायु
- प्रदूषण नियंत्रण एवं स्वास्थ्य प्रद हवा (नेशनल क्लीन एयर प्रोजेक्ट)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

ODF+ के अन्तर्गत खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना।

ODF++ के अन्तर्गत अपशिष्ट प्रबंधन के लक्ष्य को प्राप्त करना।

इसके साथ ही शौचालयों के बढ़ते प्रयोग द्वारा सीवरों की सफाई, हुई सफाई एवं मल-जल का प्रबन्धन, ~~विस्तृत~~ फीकल स्लज प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों हेतु कार्य करना बाकि है।

वस्तुतः स्वच्छ भारत अभियान अभी प्रथम चरण में है मल अपशिष्ट के निस्तारण संबंधी पहलू हेतु अभी कार्य शेष है जिसे समाप्ति करने पर 'स्वच्छता' के वृहित आयाम की प्राप्ति संभव हो पाएगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Highlight the salient features of Mission Indradhanush. What are the challenges that the mission is facing in its implementation? Suggest measures to address these challenges for progressing towards full immunization coverage. **(250 words) 15**

मिशन इन्द्रधनुष की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके कार्यान्वयन में मिशन को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? संपूर्ण टीकाकरण प्राप्ति की दिशा में प्रगति करने हेतु इन चुनौतियों को दूर करने के उपायों का सुझाव दीजिए।

भारत सरकार बच्चों में ~~मृत्यु~~ नवजात मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने हेतु टीकाकरण अभियान के रूप में मिशन इन्द्रधनुष (MI) की शुरुआत की गयी।

MI की प्रमुख विशेषताएं -

1) यह पूर्णतः केन्द्र द्वारा पोषित योजना है एवं निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा प्रदान करता है।

2) यह उन जिलों का चिन्हीकरण करता है जहां बच्चे टीकाकरण में छूट गए हैं एवं वंचित लोगों को कवर करने का प्रयास करता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3) महत्वपूर्ण प्राणघातक बीमारियों जैसे, रूबेला, डिप्थीरिया इत्यादि के टीके इसमें शामिल किए गए हैं।

कार्यान्वयन में चुनौती

1) टीकों एवं दवा के संरक्षण सम्बंधी अवसंरचना का न पाया जाना एवं औषधि का खराब होना
2) दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की सीमित पैठ एवं 'आशा' कार्यकर्ता का अनुपात होना
3) लोगों में व्याप्त भ्रांतियों एवं टीकाकरण का विरोध
4) बच्चों की पहचान की समस्या एवं टीकाकरण से छूट जाना
5) किसी तत्पर पुरस्कार के अभाव में जनता द्वारा सहयोग न किया जाना

समाधान

1) क्रियान्वयन हेतु पंचायत इकाईयों का सहयोग प्राप्त किया जाए

2) e-जॉब पोर्टल से जोड़कर सतत आपूर्ति का सुनिश्चय

3) कुछ मौद्रिक लाभ को इससे जोड़ा जाए

4) 'आशा' कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण उपाय

5) आंकड़ों को दूर करने हेतु NGO, नागरिक समाज एवं स्थानीय नेताओं का सहयोग लिया जाए।

वस्तुतः मां भारत में लोगों को रोगों के आर्थिक बोझ से बचाने एवं सुविधाओं के पूर्ण उपयोग हेतु महत्वपूर्ण है यह भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण घटक है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Assess the importance of skilling in light of changing economic and demographic structure in India. In this regard, how far has the Skill India Mission succeeded in its mandate. **(250 words) 15**

भारत में बदलती आर्थिक और जनसांख्यिकीय संरचना के आलोक में कौशल सृजन के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। इस संबंध में, स्किल इंडिया मिशन अपने अधिदेश में कितना सफल रहा है।

भारत में जनसंख्या का 55% से अधिक का आयुवर्ग क्रियाशील जनसंख्या का भाग है किन्तु भारत में केवल 4% कामगारों को किसी प्रकार का औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त है जो अन्य स्पर्धी देशों की तुलना में बहुत कम है।

बदलती आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय संरचना

आयु वर्ग	वर्तमान 2011	भावी 2041
0-19	41%	25%
19-59	52.2%	58.8%
60+	6.8%	16.2%

← 30 वर्षीय जनांकिकीय लाभांश

भारत की जनांकिकीय लाभांश की अवस्था को उठाने हेतु रोजगार प्रधान आर्थिक विकास की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कौशल सृजन का महत्व

* रोजगार की प्राप्ति एवं कौशल के आधार पर उपयुक्त, विकसित कर रोजगारों का सृजन संभव।

* कौशल एवं नवाचार के आधार पर 'मजदूरी में वृद्धि' (इन्क्रिमेन्टल) एवं जीवन स्तर में सुधार

* भारतीय श्रम की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में सुधार एवं भारतीय उत्पादों का लागत एवं श्रम प्रभावी होना

* जीरो डिफेक्ट - जीरो इफेक्ट की प्राप्ति संभव

* ऑटोमेशन, AI, औद्योगिकरण 4.0 का सामना करने में सक्षमता बढ़ाना एवं डम्ब स्किल के बजाय एबिलिटी - स्किल पर बल

* कौशल विकास के आधार पर वैश्विक श्रम-आपूर्ति श्रृंखला का भाग बनना।

भारत में कौशलता विकास हेतु कौशल भारत अभियान द्वारा 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को स्किल प्रदान करना एवं साथ ही मौलिक लोक-प्रसार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मूल्यांकन

(SI) स्किल इण्डिया मिशन टॉप डाउन एप्रोच होने के कारण तेज आधारित कौशल प्रदान करने में विफल रही है।

- SI का मूल्यांकन एवं निगरानी हेतु निरंतर अधिकारिक पुख्ता नहीं है।
- क्षेत्रीय परिषदों की कार्यक्षमता में सुधार की आवश्यकता है (शारदा प्रसाद समिति)
- नाममात्र के कौशल विकास संस्थान एवं केवल पुरस्कार राशि हेतु पंजीकरण क्योंकि परीक्षा का अभाव।

वस्तुतः इस सम्बन्ध में बताये गए मानकों का निष्पक्ष परीक्षण एवं रोजगार नियोजन के आधार पर स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है।

19. What according to you are the reasons that motivated India to create a dedicated Indo-Pacific division in the MEA recently? Also, highlight the challenges for India in the Indo-Pacific region. **(250 words) 15**

आपके अनुसार वे कौन-से कारण हैं जिन्होंने हाल ही में भारत को MEA के तहत एक समर्पित भारत-प्रशांत प्रभाग सृजित करने के लिए प्रेरित किया? साथ ही, भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत के समक्ष चुनौतियों पर भी प्रकाश डालिए।

भारत - अमेरिका के राजनीतिक सम्बंधों की घनिष्ठता के चलते पिछले कुछ समय से भारत-प्रशान्त शब्द काफी लोकप्रिय रहा है

भारत द्वारा MEA के तहत भारत द्वारा भारत-प्रशांत (IP) प्रभाग सृजित करने के कारण –

1) चीन को प्रति संतुलित करना एवं अमेरिका एवं प्रशान्त महासागरीय देशों के सहयोग से चीनी आक्रामक विरोध नीति का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना

2) हिन्द महासागर में 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' की भूमिका को रेखांकित करना

3) क्वाड QUAD संगठन की महत्ता को बढ़ाना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4) भारत APEC का सदस्य नहीं है भारत इण्डो-पैसेफिक की संकल्पना द्वारा यह हितलाभ प्राप्त कर सकता है।

5) यह प्रभाग रणनीतिक रूप हिन्द महासागर एवं प्रशान्त महासागर के रणनीतिक एकीकरण का आधार प्रदान करेगा।

भारत प्रशान्त क्षेत्र में भारत की चुनौतियाँ

① चीन की मुक्तामाल रणनीति एवं हिन्द महासागर के सीमावर्ती एवं द्वीपीय राष्ट्रों को ऋण जाल में फाँसना जबकि भारत की विकास-सहायता कूटनीति चीन की तुलना में बहुत कम

② इसके साथ ही वन बेल्ट-वन रोड द्वारा चीन की बढ़ती हिन्द महासागरीय उपस्थिति

③ भारत द्वारा Indo-Pac क्षेत्र में इण्डिया-प्रॉमिस - चाइना डिलेमा के दृष्टिकोण को

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

तोड़ने की चुनौती

4) अमेरिका के साथ आर्थिक सम्बंध राजनीतिक सम्बंधों के समान नहीं साथ ही अमेरिकी निगमों की विश्वसनीयता

5) प्रशान्त क्षेत्र की भौगोलिक दूरी एवं राजनीतिक माहौल की क्लिष्टता

6) भारत की नौसैन्य क्षमता एवं हिन्द क्षेत्र का आकार एवं खतरों का आयाम अधिक होना।

वस्तुतः हिन्द प्रशान्त संकल्पना वास्तव में वैश्विक राजनीति में भारत को महत्वपूर्ण अंश दिलाने में सहयोगी होगी किंतु इसके साथ ही इसके भारी राजनीतिक एवं आर्थिक निवेश की आवश्यकता होगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. For SCO to become a successful regional grouping, it has to overcome bilateral differences between its members and their respective geopolitical calculations. Comment. Also, discuss the role that SCO can play in enhancing India's interest in the Eurasian region. **(250 words) 15**

SCO को एक सफल क्षेत्रीय समूह बनने हेतु, अपने सदस्यों के मध्य के द्विपक्षीय मतभेदों और उनके संबंधित भू-राजनीतिक अपेक्षाओं से उबरना होगा। टिप्पणी कीजिए। साथ ही, यूरेशियाई क्षेत्र में भारत के हितों को बढ़ाने में SCO द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका की भी विवेचना कीजिए।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) चीन, रूस, कजाकस्तान, तजाकिस्तान, ~~[illegible]~~ उज्बेकिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान इत्यादि देशों का समूह है जो राजनीतिक एवं सैन्य स्तर पर शांति एवं सहयोग के लक्ष्य पर केन्द्रित है।

SCO की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी व्यवस्था (RATS) द्वारा आतंकवाद नियंत्रण किन्तु इस संगठन के सदस्य देशों में आपसी मतभेद अधिक हैं जो इसके विषय-क्षेत्र एवं आयाम में विकास को रोक रहा है।

उदा.- भारत का पाकिस्तान एवं चीन के साथ सीमा विवाद
साथ ही प्रतिसंतुलन की नीतियों द्वारा परस्पर अविश्वास

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

वस्तुतः यदि SCO के सदस्य अपने द्विपक्षीय सीमा एवं राजनैतिक विवादों का समाधान कर लेते हैं तो इस क्षेत्र में राजनीतिक तनाव की समाप्ति के चलते क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक-एकीकरण सम्बन्धी कई लक्ष्य उपलब्ध हो सकते हैं।

SCO की सफलता हेतु आवश्यक है विवादों से परे परस्पर सहमति आधारित रणनीति निर्माण एवं सहयोग द्वारा क्षेत्रीय समस्या अफगा, आतंकवाद, गरीबी का सामना किया जाए एवं क्षेत्रीय दृष्टिकोण का निर्माण हो।

यूरेशियाई क्षेत्र में भारत के हित

1) यूरेनियम एवं ऊर्जा संसाधन (गैस) (तापी)
2) वस्तु एवं सेवा व्यापार हेतु बाजार
3) रणनीतिक महत्ता एवं वैश्विक राजनीति में सहयोग

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

SCO की संभावित एवं वांछित भूमिका

1) मध्य एशिया से भारत का जुड़ाव एवं सम्पर्कता हेतु मंच की प्राप्ति द्वारा (कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया रणनीति के लक्ष्य की प्राप्ति

2) भारत के दृष्टिकोण से वैश्विक राजनीति के बारे में SCO के सदस्यों का परिचय

3) क्षेत्रीय एकीकरण एवं शांति को बढ़ावा देकर सम्बंधों का आधार स्थापित करना

4) SCO के संयुक्त कार्यक्रम क्रियान्वयन के सम्बंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर एवं भारत को प्रदर्शन का अवसर।

इस प्रकार SCO भारत हेतु मध्य एशिया एवं यूरेशिया में प्रवेश-द्वार के रूप में महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत द्वारा इन अवसरों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए।